# बिहार गजट
## असाधारण अंक
### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 आश्विन 1939 (१०) ।
(सं० पटना ९८०) पटना, वुधवार, १८ अक्टूबर २०१७ ।

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना ।
18 अक्टूबर 2017 ।
अधिसूचना सं० 39/2017- राज्य कर (दर) ।

ए० ओ० 245, दिनांक १८ अक्टूबर २०१७— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का बिहार अधिनियम १२) की धारा ९ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आयार पर, माल जिनका विवरण निम्न तालिका के स्तंभ (३) में विनिर्देश हैं तथा जो उपलब्ध तालिका के स्तंभ (२) में तत्कालीन प्रविधि में यथा विनिर्देश, यथास्थिति, टर्फ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अधिकार के अंतर्गत आता है, राज्य के भीतर आपूर्ति पर, २.५ प्रतिशत की राज्य कर की दर सुचित करते हैं, पर नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (४) में विनिर्देश शर्त के अंतर्गत यथा:-

## तालिका

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रम सं</th>
<th>अन्वेषण उपशीर्ष/शीर्ष/टर्फ मद</th>
<th>माल का विवरण</th>
<th>शर्त</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(१)</td>
<td>(२)</td>
<td>(३)</td>
<td>(४)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 1.     | 19 or 21                      | केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किसी कार्यक्रम के अंतिम समाप्ति | यदि खास निम्नलिखित का प्रदायक ऐसे किसी अधिकारी से, जो भारत सरकार के उप सचिव की पंक्ति से नीचे का नहीं है या सबसे अधिक राज्य सरकार में उप सचिव की पंक्ति से नीचे का नहीं, इस आश्रय
<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रम सं.</th>
<th>अध्याय</th>
<th>माल का विवरण</th>
<th>शर्त</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(1)</td>
<td>(2)</td>
<td>(3)</td>
<td>(4)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को निशुल्क वित्तपंश के लिए आशयित और यूनिट अभियानों में रखी गई खाता निर्मितियाँ।

आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि ऐसी खाता निर्मितियाँ केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किसी कार्यक्रम के अधीन समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को ऐसे माल की आपूर्ति की तारीख से पांच मास की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय कर आयुक्त के इस निर्मित निमित्त अनुमान करे। वितरित कर दी गई है।

स्पष्टीकरण--

(i) “टैरिफ मद”, “उपशीर्ष”, “शीर्ष” और “अध्याय” से सीमाधार्मिक टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा।

(ii) उक्त सीमाधार्मिक टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के अनुसार और अध्याय टिप्पणि तथा साधारण स्पष्टीकरण टिप्पणि भी हैं, के निर्यात के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्यात के लिए लागू होंगे।

[(सं.सं.वि.की.कर / जी.एस.टी. / विषय-21/2017-39)]

भिक्षार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्राचार सचिव।

18 अक्टूबर 2017

एस.ओ. आर्जो 246, एस.ओ. आर्जो 245, दिनांक 18 अक्टूबर 2017 का अंग्रेज़ी में निम्नलिखित अनुवाद भिक्षार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेज़ी मौष में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं.सं.वि.की.कर / जी.एस.टी. / विषय-21/2017-39)]

भिक्षार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्राचार सचिव।
The 18th October 2017
Notification No.- 39/2017- State Tax (Rate)

S.O. 245, dated 18th October 2017—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 9 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby notifies the State tax rate of 2.5 per cent on intra-State supplies of goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2), subject to the condition specified in column (4) of the Table below, namely:-

Table

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sl. No.</th>
<th>Tariff item, sub-heading, heading or Chapter</th>
<th>Description of Goods</th>
<th>Condition</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>19 or 21</td>
<td>Food preparations put up in unit containers and intended for free distribution to economically weaker sections of the society under a programme duly approved by the Central Government or any State Government.</td>
<td>When the supplier of such food preparations produces a certificate from an officer not below the rank of the Deputy Secretary to the Government of India or the Deputy Secretary to the State Government concerned to the effect that such food preparations have been distributed free to the economically weaker sections of the society under a programme duly approved by the Central Government or the State Government concerned, within a period of five months from the date of supply of such goods or within such further period as the jurisdictional commissioner of the Central tax or jurisdictional commissioner of the State tax, as the case maybe, may allow in this regard.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Explanation. –

(1) In this notification, “tariff item”, “sub-heading” “heading” and “Chapter” shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).
(2) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975, including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-21 /2017-39)]

By the order of Governor of Bihar,
Sujata Chaturvedi,
Commissioner-cum-Principal Secretary,
Commercial Taxes Department.

चित्रकुट, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 980-571+10-डीटीपी01

Website: http://egazette.bih.nic.in